



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:20429

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ**

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 12020/2024

सत्यराम गुप्ता

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: शैलेंद्र पाठक, पायल सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 23

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।
2. यह आवेदक की ओर से दायर की गई पहली जमानत याचिका है, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20 के तहत केस क्राइम संख्या 0014/2024, पुलिस स्टेशन- जरवा, जिला- बलरामपुर में आरोपी है।
3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, यानी 1.658 ग्राम चरस बरामद होने की बात कही गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50, 52A और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है। फर्द बरामदगी के समर्थन में कोई भी सार्वजनिक या स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.02.2024 से जेल में बंद है। इसके अलावा, यह भी निवेदन किया गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक के भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः, आवेदक को जमानत प्रदान की जाए।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि बरामद किया गया प्रतिबंधित पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से अधिक है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि केवल वैधानिक प्रावधानों के पालन में कुछ मामूली अनियमितताओं के कारण, अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा; इसलिए, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह उसमें निर्धारित दोहरी शर्तों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करे।
7. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि (i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आवेदक कथित अपराध का दोषी नहीं है; और (ii) आवेदक के जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 में निहित दोहरी शर्तें पूरी हो गई हैं, और यह तथ्य कि बरामद प्रतिबंधित सामग्री व्यावसायिक मात्रा से थोड़ी अधिक है; आवेदक 09.02.2024 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।
9. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
10. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल आवेदक- **सत्यराम गुप्ता** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि वह सबूतों के लिए तय तारीखों पर, जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने हर तय तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति होने पर, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 बी.एन.एस. एस. के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार, धारा 209 बी.एन.एस. के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत अर्जी तक ही सीमित हैं, और इनका विचारण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

20 मार्च 2026

आनंद/-

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)